बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 105 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 03 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

पेरेंट्स का इंतजार बढ़ा! दिल्ली में प्राइवेट स्कूल की फीस पर बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने क्या बताया?

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करने वाला कानून चालू वर्ष में नहीं बल्कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा। यह घटना तब सामने आई है जब शीर्ष अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में मंगलवार को रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए निजी स्कूल शुल्क विनियमन कानून के कार्यान्वयन को स्थगित करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया था। 19 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से निजी स्कूलों की फीस तय करने वाले कानून को अप्रैल 2026 तक लागू करने पर विचार करने को कहा था।

पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अप्रकाशित किताब पर संसद में हंगामा, राहुल गांधी और राजनाथ-शाह के बीच जोरदार बहस

नई दिल्ली।

संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। नेता विपक्ष राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच तीखी बहस हुई। दरअसल, राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ की किताब का हवाला देकर चीन पर सवाल पूछना शुरू किया। इसी बीच रक्षा मंत्री ने भी जवाब देते हुए प्रमाण पेश करने की बात कही। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

राहुल गांधी ने पूछा सवाल

राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सेना भारतीय सीमा में घुस रही है। राहुल गांधी के इस बयान पर सदन में हंगामा खड़ा हो गया है। वहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को उनकी बात कहने का पूरा हक है। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी सांसद ने कहा कि हम देश भक्त नहीं हैं। इसपर मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है कि चीनी सेना भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रही है।

रक्षा मंत्री ने दिया जवाब

राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस किताब का राहुल गांधी उल्लेख कर रहे हैं, वो किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। ऐसे में इस पुस्तक का उल्लेख क्यों किया जा रहा है? राहुल गलत किताब का जिक्र कर रहे हैं। राजनाथ सिंह का कहना है कि राहुल गांधी अपने दावे को साक्ष्यों के साथ प्रमाणित करें। बिना तथ्य के उन्हें आरोप नहीं लगाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा, ÷जिस किताब की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, वो किताब प्रकाशित नहीं हुई है। अगर उस पुस्तक में तथ्य सही होते, तो वो किताब जरूर प्रकाशित होती। अगर उन्हें (राहुल गांधी) लगता है कि किताब पर सरकार ने गलत तरीके से रोक लगाई है, तो पूर्व आर्मी चीफ अदालत का दरवाजा खटखटाते।

स्पीकर ने जताई आपत्ति

राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद में बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। इसलिए मुद्दे पर बने रहें। ये सदन नियम से चलता है और बड़ी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप नियमों का पालन करते हुए बजट पर ही बात करें। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत-चीन रिश्तों का कोई जिक्र नहीं है। अभी अभिभाषण पर ही चर्चा करते हुए सदन की मर्यादा रखें। राहुल गांधी के बार-बार सवाल उठाने पर स्पीकर ने कहा, मुझे लग रहा है आज आप तय करके आए हैं कि मुझे अपनी बात नहीं रखनी है। मैं 5 बार आपको नियम बता चुका हूं।

आपसे नियमों के पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

राहुल गांधी ने दी सफाई

राहुल गांधी ने कहा, ÷सरकार विपक्ष के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाती है। वहीं, राजनाथ सिंह समेत कुछ लोगों पर जनरल नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। मेरी बात चीन के बारे में नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के कैरेक्टर के बारे में है।

स्पीकर ने याद दिलाए नियम

स्पीकर ने कहा, संसद की नियम प्रक्रिया 353 के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बोलने से पहले आपको लिखित में देना होगा। सदन नियम से चलेगा। आप अगर नहीं बोलना चाहते हैं, तो मैं अगले वक्ता के रूप में अखिलेश यादव को बुलाना चाहूंगा।

अमित शाह ने बोला हमला

राहुल गांधी के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी हमला बोला है। अमित शाह ने कहा, मैंने तेजस्वी सूर्या के भाषण को ध्यान से सुना है। उन्होंने कहीं भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए हैं। राहुल गांधी ने सदन के नियमों को भंग किया है। सत्तापक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित करने का आदेश दिया है।

चीन सीमा मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा

केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी द्वारा चीन सीमा का मुद्दा उठाने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह बताए कि क्या वह 1959 और 1962 में चीन द्वारा कब्जाई गई जमीन को वापस ला सकती है। रिजिजू ने कहा कि चीन सीमा से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस के पापों के लिए राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। किरण रिजिजू ने तीखे शब्दों में कहा क्या किसी बड़े परिवार में जन्म लेने से कोई व्यक्ति संसद और नियमों से ऊपर हो जाता है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां व्यवस्था नियमों से चलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी खुद को संसद से ऊपर समझते हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनके नियम उल्लंघन पर तालियां बजाते रहे।

सदन ने अपने ही नियम छोड़ दिए- मनोज झा

राज्यसभा सांसद और आरजेडी नेता मनोज झा ने संसद की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि सदन ने अपने ही तय किए गए नियमों से दूरी बना ली है। मनोज झा ने कहा कि उन्होंने कई मौकों पर सदन के भीतर पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशित स्रोतों का हवाला दिया है और ऐसा पहले कभी आपत्तिजनक नहीं माना गया। लेकिन मौजूदा विवाद को देखते हुए उन्हें संदेह है कि क्या पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे (सेवानिवृत्त) की अप्रकाशित आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' को भविष्य में प्रकाशित होने की अनुमति भी मिल पाएगी या नहीं।

संसद में सांसदों के अधिकार छीने जा रहे हैं- कल्याण बनर्जी

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद की कार्यप्रणाली और सत्ता पक्ष के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि बार-बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर विपक्ष के चरित्र, अस्तित्व और पहचान पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे संसदीय गरिमा को ठेस पहुंच रही है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मौजूदा हालात देखकर ऐसा लगता है मानो संसद के भीतर सांसदों के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। उनके मुताबिक, जनप्रतिनिधियों से धीरे-धीरे उनके सभी अधिकार छीने जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए सही दिशा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह रास्ता ठीक नहीं है और आने वाले समय में देश की जनता इसका जवाब जरूर देगी।

राहुल के बयान पर संसद में हंगामा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सदन में किसी अप्रकाशित किताब या संस्मरण के हवाले देना संसदीय नियमों के खिलाफ है। हालांकि, राहुल गांधी का दावा है कि उनका स्रोत भरोसेमंद है और उसमें एक पूर्व सेना अधिकारी के अप्रकाशित संस्मरणों के अंश शामिल हैं।

पहली बार ऐसा हुआ- जगदंबिका पाल

इस मुद्दे पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सांसद को एक ही बात दोहराने से पांच बार रोका गया। यह सब पूर्व नियोजित लग रहा था। उन्होंने राहुल गांधी के भाषण को शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

बजट की कलम से खुलेगा स्कूल से स्किल तक का नया अध्याय, शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार

नई दिल्ली । केंद्रीय बजट से दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। दिल्ली में नए पीएमश्री स्कूल खुलने, अटल टिंकरिंग लैब स्थापित होने, पीएम पोषण योजना का दायरा बढ़ने सहित दूसरी योजनाओं के पूरा होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अटल टिंकरिंग लैब योजना के लिए 3200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। पिछले संशोधित बजट में यह राशि 500 करोड़ रुपये थी। स्कूलों में लैब के स्थापित होने से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के अलग-अलग स्कूलों में 450 से अधिक टिंकरिंग लैब स्थापित है। बजट में पीएम पोषणा योजना की धनराशि में भी इजाफा किया गया। इसका लाभ भी दिल्ली के स्कूलों को मिलने की उम्मीद है। इस बार बजट में 12750 रुपये आवंटित किए गए। जबकि पिछले वर्ष संशोधित बजट में यह राशि 10600 करोड़ रुपये थी। इसी प्रकार से पीएमश्री स्कूल के लिए बजट में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7500 करोड़ रुपये आवंटित की गई। जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4500 करोड़ रुपये संशोधित बजट आवंटित किया गया था। बजट राशि के बढ़ने से दिल्ली में पीएमश्री स्कूलों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। स्कूलों में प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ध्रुव योजना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये आवंटित हुए। इसका लाभ दिल्ली के प्रतिभाशाली बच्चों को मिल सकेगा। एनसीईआरटी के लिए बजट में 58.63 करोड़ रुपये की राशि का इजाफा किया गया। पिछले वर्ष 623.16 करोड़ रुपये का संशोधित बजट जारी किया गया था। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए बजट में 160 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। पिछले वर्ष की तुलना में 9.5 करोड़ रुपये का इजाफा। शिक्षा बजट में देशभर के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) के लिए 169.06 करोड़ रुपये आवंटित हुए। शिक्षा बजट में केंद्र सरकार के अधीन संचालित होने वाले विश्वविद्यालयों को आवंटित बजट का कोई विवरण नहीं दिया गया। इसमें दिल्ली विवि, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया शामिल है। साथ ही आईआईटी दिल्ली को लेकर बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। एजुकेशन टाउनशिप बनने से शिक्षा क्षेत्र को नई रफ्तार मिलेगी। छात्राओं के लिए हर जिले में हॉस्टल की व्यवस्था होने से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। शहरों में पढ़ाई के लिए किराये का भार कम होगा। युवाओं को कौशल बनाने पर सरकार का ध्यान केंद्रित है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ने का सुनहरा मौका उपलब्ध कराया जा रहा है। -दीप्ति तनेजा, इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय।

बजट में घोषित विश्वविद्यालय टाउनशिप में नरेला शिक्षा केंद्र को शामिल कराने की कोशिश करेंगे : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार प्रस्तावित नरेला शिक्षा केंद्र को इस वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित पांच नयी विश्वविद्यालय टाउनशिप में शामिल कराने की कोशिश करेगी। गुप्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बजट संतुलित है और इसने देश की महिलाओं तथा युवाओं सहित हर वर्ग एवं श्रेणी को अवसर प्रदान किए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले बजट में दिल्ली, पुडुचेरी के लिए पूंजीगत हस्तांतरण के वास्ते रायों को दी जाने वाली विशेष सहायता 6,275 करोड़ रुपये थी, जो 2026-27 के बजट में बढ़कर 15,380 करोड़ रुपये कर दी गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली बजट प्रावधानों का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि 2025-26 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत 12,483 करोड़ रुपये के मुकाबले इस बार 13,611 करोड़ रुपये का आवंटन होने से दिल्ली को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिनमें हर जिले में बालिकाओं के लिए छात्रावास, स्वच्छ ऊर्जा प्रोत्साहन और दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों के लिए बढ़ाई गई धनराशि शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे शहर के लाखों लोगों को सीधे लाभ होगा। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली-वाराणसी उच्च गति रेल गलियारे की घोषणा से राष्ट्रीय राजधानी में परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली बजट घोषणा का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करेगी ताकि परिसरों में कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशालाएं खोली जा सकें और एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों को जोड़ा जा सके।

पुणे के पोर्श हादसा मामले में बड़ा फैसला, तीन आरोपियों को जमानत मिली; 2024 में हुई थी दो मौतें

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के चर्चित पुणे पोर्श कार हादसा मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। इस हादसे में दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने इस दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में माता-पिता की जिम्मेदारी भी तय होती है, क्योंकि वे अपने नाबालिग बच्चों पर सही नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा, नशे की समस्या अलग बात है, लेकिन बच्चों को कार की चाबियां और खुला पैसा देना ताकि वे ऐश कर सकें, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है।

अमर संतोष गायकवाड़- आरोप है कि उसने तीन लाख रुपये देकर एक डॉक्टर के सहायक के जरिए नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलवाया। आदित्य अविनाश सूद और आशीष सतीश मित्तल- इनके खून के सैंपल जांच में इस्तेमाल किए गए थे, जबकि वे कार में मौजूद दो नाबालिगों से जुड़े बताए गए। इससे पहले दिसंबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अमर गायकवाड़ समेत आठ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था और अब तीनों को जमानत दे दी गई है। इस मामले में ब्लड सैंपल बदलने के मामले में कुल 10 लोगों को जेल भेजा गया था, जिनमें नाबालिग के माता-पिता विशाल अग्रवाल और शिवानी अग्रवाल, डॉक्टर अजय तावरे और श्रीहरी हालनोर, ससून अस्पताल का कर्मचारी अतुल घाटकांबले, और दो बिचौलिए शामिल हैं। पुणे शहर में 18-19 मई 2024 की दरम्यानी रात को करीब तीन करोड़ रुपये की पोर्श कार को तेज गति से दौड़ाने के चक्कर में 17 साल के लड़के ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी। गाड़ी की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक अपना संतुलन खोकर काफी दूर तक सड़क पर घिसटते चली गई, जिससे उस पर सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के 14 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी।

ये क्या तरीका है?, संसद में हंगामे के बीच वेणुगोपाल पर भड़के स्पीकर ओम बिरला, राहुल गांधी से हुई बहस

नई दिल्ली।

संसद के बजट सत्र के दौरान आज सदन में पक्ष और विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र किया, जिसे लेकर सत्तापक्ष भी भड़क उठा। इसी बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को फटकार लगा दी। संसद में जोरदार हंगामे के बीच जब राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब का नाम लिया, तो केसी वेणुगोपाल खड़े होकर तालियां बजाने लगे। यही नहीं, वो जोर-जोर से चिल्लाने भी लगे। उनके इस रवैये पर स्पीकर ओम बिरला ने सख्त नाराजगी जताई है। ओम बिरला ने केसी वेणुगोपाल को फटकार लगाते हुए कहा, ये क्या तरीका है? आप सदन में खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं। केसी वेणुगोपाल के बर्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए ओम बिरला ने कहा, आप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वकील हैं? इसपर वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस का हर सदस्य राहुल गांधी का वकील है। वेणुगोपाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ओम बिरला ने कहा- यहां वकीलों को बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है। यहां सदन के माननीय सदस्य गण ही बोल सकते हैं। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को मुद्दे से न भटकते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात करने की सलाह दी। इसपर राहुल गांधी ने कहा, ÷सर आप एक काम करिए कि आप ही बता दीजिए कि मुझे क्या बोलना है? राहुल गांधी के सवाल पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा- मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन स्पीकर के नाते मेरा दायित्व है कि ये सदन नियम प्रक्रियाओं से चले और जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उसी पर बात करें। जब सत्तापक्ष के सदस्य चर्चा से इतर बोल रहे थे, तब मैंने उनको भी रोका था। आप बड़ी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप सदन की मर्यादा बनाए रखें।

भारत-विभाजन के नए अध्याय

बात दिल्ली के बहावलपुर-हाउस या पंजाब-हरियाणा में स्थापित बहावलपुर-भवनों तक सीमित नहीं, न ही यह किस्सा वर्तमान पाक के बहावलपुर तक सीमित है। अब इतिहास के कुछ अछूते पृष्ठ भी खुलने हैं। इन्हें गर्व है अपनी संस्कृति, अपनी मां-बोली और अतीत की धर्मनिरपेक्ष जिंदगी पर। एक समय था इनके बहावलपुर के नवाब ने नवनिर्मित पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जिन्ना को शुरुआती दौर में वर्ष 1947 में 7 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया था ताकि नए मुल्क के स्टाफ को दो माह का वेतन तो मिल सके। मगर इन्हें आज इस बात की शर्मिंदगी है कि उनका बहावलपुर इन दिनों 'जैश' व लश्कर-तैयबा सरीखे आतंकी संगठनों का केंद्र बना हुआ है। 'ऑपरेशन सिन्दूर' के मध्य जिन आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना के जवानों ने ठोका था, उनमें बहावलपुर के ये शिविर भी शामिल थे। हाल ही में कुरुक्षेत्र के एक फोटो जर्नलिस्ट एवं सोशल मीडिया कर्मी कमल मेहता ने महाराष्ट्र के धुलिया नामक शहर में बसे लगभग 4000 बहावलपुरी लोगों से भेंट की। कमल मेहता वहां बसे बहावलपुरी परिवारों की मुखिया से जोड़ने के लिए वहां गया तो भारत-विभाजन के नए अध्याय भी खुले। देश को आजाद हुए 78 साल होने को है, लेकिन आज भी विभाजन का बेताल हमारे कंधों पर चढ़ा हुआ है, जिसे उतारने की कोशिश न तो हमारे बुजुर्गों ने की और न ही हमारी आने वाली नस्लें कर रही हैं। विभाजन के समय बहावलपुर (अब पाक में) से भारत में आ बसे परिवारों में कई सारी बिरादरी आई और इन्हीं में से एक बिरादरी का नाम है बहावलपुर बिरादरी। इस बिरादरी का जब भी जिक्र आता है तो पहले श्रीगंगानगर की याद आती है जहां सबसे ज्यादा बहावलपुर के लोग वहां आकर बसे थे क्योंकि यह भारत-पाक सरहद के बिल्कुल नजदीक था। उसके अलावा एनसीआर का जिक्र आता है जो कि छोटा बहावलपुर माना जाता है उसके बाद अलग-अलग शहरों में भी कुछ लोग है लेकिन वह रोजगार और रिश्तेदारियों की वजह से धीरे-धीरे वहां स्थानांतरित हुए। बीकानेर में भी बहावलपुर रियासत से आये हुए परिवारों ने अपने घर बनाए अपने परिवारों को वहां पर स्थाई रूप से एक आशियाना मिला और यहीं पर स्थापित होकर अपनी पहचान बना ली है। अब हर जगह एक बहावलपुर नगरी है या एक बहावलपुरी सभा है। उसी बहावलपुर के लगभग 4000 लोग, महाराष्ट्र जलगांव से 100 किलोमीटर दूर धुलिया नामक शहर में आ बसे थे। अचंभा होता है कि महाराष्ट्र में ये लोग कैसे चले गए इनकी दास्तान कुछ यूं सामने आती है। पश्चिम पाकिस्तान की बहावलपुर स्टेट के खानपुर नाम के जिले में सदीकाबाद नाम की तहसील है जो आज भी कायम है उसी तहसील में एक छोटा सा गांव था संजरपुर जो आज भी है, जिसके ये लोग निवासी थे। ये बताते हैं कि, 'उसी गांव में हम हिंदू और मुसलमान सदियों से भाईचारे से अपना निर्वाह भलीभांति कर रहे थे। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था प्रत्येक समाज अपने धर्म के अनुसार पूजा-अर्चना करता था, जीवन अच्छी तरह व्यतीत हो रहा था कि अचानक 14 अगस्त 1947 में तूफान आया और देखते ही देखते भारत के दो भाग हो गए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। विभाजन के नाम पर वहां के लोगों में 'नफरत अचानक सुलगी। वहां के मुसलमानों ने हम हिंदुओं को बुरी तरह से मार-पीट कर अपने देश से निकाल दिया।' 'संजरपुर गांव सिंध-पंजाब की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण कामकाजी गांव था, वहां की जमीन उपजाऊ थी, 'आबादी 150 से 200 परिवारों की थी जिसमें 40 प्रतिशत हिंदू और 60 प्रतिशत मुसलमानों के परिवार थे। हमारे गांव के नजदीक डंडी, कोट, अहमदपुर, भुंग, बल्लार आदि छोटे-छोटे गांव थे। उनमें बल्लार रेल वे स्टेशन था।' तब हालात को बिगड़ते देख बहावलपुर समाज के मुखी लाला सत्यरामदास रेलन ने बिरादरी प्रमुखों की एक मीटिंग बुला ली और मौलवियों द्वारा दी धमकियों का ब्यौरा दिया। इस सारे विषय पर गंभीरता से सभी ने विचार कर एक सहमति से गांव की सुरक्षा के लिए और अपने बचाव के लिए वहां के खान साहब से मदद मांगी। वे 5 अक्तूबर 1947 सुबह ठीक 10 बजे मुखी साहब अपने शिष्टमंडल के साथ खान साहब के बंगले पर पहुंच गए। खान साहब ने सब का स्वागत किया, वे 'वालेकुम अस्सलाम' कह कर सब खान साहब के साथ बैठ गए। मुखी ने गांव में हो रहे दंगों के बारे में गांव की सुरक्षा के बारे में विनती की। खान साहब ने कबूल किया कि वह जो हो रहा था, सब गलत हो रहा था। यह सिर्फ अपने गांव में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के हर शहर और गांवों में अत्याचार, खून-खराबा और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, जिस पर पाकिस्तान की सरकार काबू नहीं पा रही है। हालात सुधरने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं आप को यह सलाह देता हूं कि जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक आप यहीं पर रहें, तब तक के लिए मैं सुरक्षा के इंतजाम करता हूं और यह भी सलाह देता हूं कि मामला शांत होने के बाद आप लोग बाल-बच्चों सहित अपने वतन हिन्दुस्तान (भारत) चले जाओ। आप को सुख से भारत पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी आप लोग मुझ पर विश्वास रखो, मैं अपने गांव का एक परिंदा भी नहीं मरने दूंगा। आप लोगों को मैं बाल-बच्चों सहित भारत पहुंचाऊंगा।' खान साहब के आश्वासन पर भरोसा कर समाज के मुखिया सत्यरामदास रेलन ने 12 अक्तूबर 1947 को धर्मशाला में समाज की आम सभा बुलाई। सब के विचारों के अनुसार आमराय बनी कि हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए अपनी संस्कृति और मां-बहनों की लाज बचाने के लिए हमें अपनी जन्मभूमि छोड़ना भी पड़े तो भी हमें कबूल है।' सब ने एक ही आवाज में कहा कि वतन बदल सकते हैं, धर्म हरगिज नहीं बदलेंगे। सब की एक राय पर सदियों से रह रहे अपने संजरपुर गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। हिन्दुस्तान में हमें कब, कहां और कैसे जाना होगा यह निश्चित करने के लिए ही एक कमेटी बनी और खान अब्दुल वाहिद खान अब्बासी की अध्यक्षता में 21 पंचों की एक सुरक्षा कमेटी बनाई गई। सुरक्षा कमेटी में कई बिरादरियों के प्रमुख कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया। सुरक्षा कमेटी में तय हुआ कि मार्च 1948 तक हमें पाकिस्तान छोड़कर कराची के रास्ते हिन्द महासागर लांघकर सौराष्ट्र होते हुए पानी के जहाज में बैठकर गुजरात राजस्थान सीमा पार करके बम्बई बंदरगाह जाना है या रेलवे द्वारा सफर कर के नजदीक पाकिस्तान सीमा पार कर सौराष्ट्र या गुजरात के किसी अच्छे शहर में डेरा डाला जाए। खान साहब की सलाह के अनुसार, पाकिस्तान छोड़ने की योजना बनाई गई क्योंकि उनकी दोनों जगह अच्छी मान्यता थी। वह जो भी निर्णय लेते थे दोनों समाज उसे स्वीकार करते थे।

अर्थव्यवस्था बनाने का सपना

वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में रखा गया आगामी वित्त वर्ष 2026-27 का बजट वास्तव में ऐतिहासिक बजट कहा जा सकता है क्योंकि इसमें भविष्य के भारत की तस्वीर का सपना संजोया गया है और 2047 तक विश्व व्यापार में भारत के दस प्रतिशत हिस्से की कल्पना की गई है।

अतः यह जरूरी था कि विकासशील बजट के माध्यम से ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना पालतों जिसमें भारत के खेतों से लेकर अन्तरिक्ष तक के क्षेत्र में विकास की गंगा बहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध व विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त हो सके। वास्तव में यह बजट दूरगामी आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का ऐसा दस्तावेज है जिसमें युवा पीढ़ी के सपनों को मूर्त रूप देने की कोशिश की गई है। इस सिलसिले में वित्तमंत्री ने जिस प्रकार परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र से लेकर कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) तक के क्षेत्र में विभिन्न उपायों की व्यवस्था की है उससे यही साबित होता है कि भारत अब विश्व के मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के मार्ग में पीछे नहीं हटेगा मगर इस लक्ष्य की तात्कालिक आवश्यकताओं की आपूर्ति किये बिना हासिल नहीं किया जा सकता है और इस सन्दर्भ में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में रोजगार के साधनों में प्रचुरता आये। इस दृष्टि से यह बजट घरेलू अर्थव्यवस्था के आर्थिक मानकों को मजबूती देने का काम करेगा क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक में पूंजीनिवेश को बढ़ावा देने के उपाय किये गये हैं और साथ ही बदलते भारत की हकीकत को ध्यान में रखा गया है। इस मामले में वित्तमंत्री ने मध्यम व औसत दर्जे के बढ़ते शहरों की संख्या को देखते हुए म्युनिसिपल बांड जारी करने की प्रथा को गति देने के लिए जो उपाय किये हैं वे इस तथ्य की ओर इंगित करते है कि 2030 तक भारत की 40 प्रतिशत आबादी के शहरों में बसने से जीवन की सहजता बरकरार रह सके। इसीलिए शायद सबसे ज्यादा जोर बजट में आम आदमी के जीवन को सुगम बनाने पर दिया गया है और पेन्शंस आयकर के नियमों में इस प्रकार संशोधन किये गये हैं जिससे आयकर देने वाले लोगों के सिर से भारी सजा व जुर्माने का डर समाप्त हो सके। यह कदम देश में आयकरदाताओं की संख्या बढ़ाने में कारगर होगा और ईमानदारी के साथ कर जमा कराने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। बजट इस बात का भी सबूत है कि भारत सभी अर्थों में वैश्विक अर्थव्यवस्था का अंग बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है क्योंकि इसमें भारत में व्यापार करने वाले लोगों को सहज व सुगम वातावरण देने के व्यापक उपाय किये गये हैं। कुछ लोग इस बात की आलोचना कर सकते हैं। संसद में बजट पेश होते ही शेयर बाजार धड़ाम हो गया और इसमें भारी मुनाफा वसूली शुरू हो गई। ऐसा मूलतः शेयरों की खरीद-फरोख्त पर लागू किये गये नये शुल्क नियमों की वजह से ही हुआ। इससे यही साबित होता है कि कार्पोरेट क्षेत्र ने बजट को आम गरीब व मध्यम वर्ग का बजट समझा। यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जबकि पूरा विश्व भारी उथल-पुथल के मुहाने पर बैठा हुआ है जिसके चलते आर्थिक मानक अस्थिर बने हुए हैं। अतः इस दौर में यदि भारत अपनी अर्थव्यवस्था के मानकों की जड़ से मजबूत बनाने के प्रयास करता है उससे इस देश को आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्ज्वल होगा। आम आदमी के लिए यह बजट सबसे ज्यादा खुशी महंगाई के मोर्चे पर लेकर ही आया है। बजट में जो विभिन्न उपाय किये गये हैं और किसी भी क्षेत्र में शुल्क की वृद्धि नहीं की गई है उससे मुद्रास्फीति की दर काबू में रहेगी और आम उपभोक्ता सामग्री के दामों में वृद्धि नहीं होगी। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कुल साढ़े 53 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें 35 लाख करोड़ से अधिक की राजस्व प्राप्तियां होंगी। इसलिए सरकार जरूरत पड़ने पर इसकी भरपाई बाजार से ऋण आदि लेकर करेगी। जरा कल्पना कीजिये जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तो इसका कुल बजट (रेलवे के अलावा) केवल 259 करोड़? रुपए का था जो आज बढ़कर 53 लाख करोड़? रुपए (रेलवे समेत) हो चुका है और इसकी आबादी 30 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ की हो चुकी है। जाहिर है कि इस दौरान हमने जबरदस्त विकास किया है जिसकी वजह से आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मगर इस दौरान हम संरक्षित अर्थव्यवस्था से निकल कर बाजार मूलक अर्थव्यवस्था भी बन चुके हैं जिससे भारत की आर्थिक चुनौतियों में गुणात्मक अन्तर आया है। इन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती रोजगार के सृजन की होती है अतः वित्तमंत्री ने मौजूदा बजट में सबसे ज्यादा जोर इसी पक्ष पर देते हुए बदलते युग की उत्पादन आवश्यकताओं पर बल दिया है और पर्यटन के क्षेत्र से लेकर आधुनिकतम उत्पादों के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उपाय किये हैं। हमें यह भी समझना होगा कि भारत के उत्पादों की विश्व मांग बढ़ाने के लिए हमें जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ानी होगी जिससे हम बदलते दौर के आयात-निर्यात कारोबार के प्रतिबन्धों के ढीला होने से अपनी जगह अपने बूते पर बना सकें। बेशक अब बजट का सम्बन्ध सीधे चीजों के सस्ता और महंगा होने से कटता जा रहा है क्योंकि इसके लिए पृथक जीएसटी की व्यवस्था है मगर आम आदमी के लिए बजट रोजी-रोटी के साधन बढ़ाने का जरिया बन चुका है क्योंकि बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में सरकार का कर्तव्य ऐसी नीतियों के निर्माण का होता जिनसे हर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सके और वह आधुनिकतम होता जाये। इस मोर्चे पर बजट आम भारतीय की अपेक्षाओं की आपूर्ति करता है।

सम्पादकीय...

'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया'

भारत -यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, जिसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' के रूप में जाना जा रहा है, लगभग 2 दशकों की लंबी वार्ताओं का परिणाम है और इसमें 2 अरब से अधिक की आबादी तथा 27 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त अर्थव्यवस्था शामिल है, जो वैश्विक जी.डी.पी. का लगभग 25 प्रतिशत है। यह समझौता भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर प्रदान करता है, विशेषकर ऐसे समय में, जब अमरीकी टैरिफ के कारण निर्यात प्रभावित हो रहा है। हालांकि, इसे प्रभावी बनाने के लिए सरकार को रणनीतिक कदम उठाने होंगे। इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ भारत में निर्यात होने वाले 96.6 प्रतिशत सामानों पर टैरिफ को समाप्त या कम करेगा, जिससे यूरोपीय कंपनियों को सालाना लगभग 4 बिलियन यूरो (लगभग 4.7 बिलियन डॉलर) की बचत होगी। भारत ने यूरोपीय संघ को 102 सेवा उप-क्षेत्रों में पहुंच प्रदान की है, जबकि यूरोपीय संघ ने भारत को 144 उप-क्षेत्रों में अवसर दिए हैं, जिनमें वित्तीय, समुद्री और दूरसंचार सेवाएं शामिल हैं। अनुमान है कि यह समझौता 2032 तक यूरोपीय संघ के भारत में निर्यात को दोगुना कर देगा। साथ ही, यह अमरीकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा, जहां भारत के श्रम-गहन निर्यात प्रभावित हो रहे हैं। माना जा रहा है कि यह समझौता 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' योजनाओं के साथ तालमेल बैठाता है। यह न केवल निर्यात को बढ़ाएगा, बल्कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निवेश और रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहित करेगा। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के साथ समझौता भारतीय एम.एस.एम.ई. को वैश्विक आपूर्ति शृंखला में शामिल होने का अवसर देगा। हालांकि, इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए चुनौतियों का सामना करना होगा। यहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफैसर अरुण कुमार की चेतावनियां प्रासंगिक हैं। प्रोफैसर कुमार, जो काले धन और आर्थिक नीतियों के विशेषज्ञ हैं, ने भारत-यूरोपीय संघ एफ.टी.ए. को 'अमरीका जैसा एक और जाल' बताया है। उन्होंने असमान शर्तों, घरेलू उद्योगों विशेषकर कृषि और डेयरी पर जोखिम, व्यापार घाटे में वृद्धि, नीति स्थान की हानि और दीर्घकालिक आर्थिक निर्भरता की चेतावनी दी है। उन्होंने अमरीकी व्यापार समझौतों से सबक लेने की सलाह दी है, जहां कृषि बाजार खोलने की मांग भारत के लिए कठिन है। इन चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को रचनात्मक कदम उठाने चाहिएं। सबसे पहले, संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। समझौते में डेयरी और कुछ कृषि उत्पादों को बाहर रखा गया है, लेकिन कुमार की चेतावनी के अनुसार, बाजार बाढ़ से बचने के लिए सख्त निगरानी तंत्र विकसित करें। सरकार कृषि क्षेत्र में सबसिडी और समर्थन को मजबूत करे, जैसे कि फसल बीमा और बाजार लिंकेज को बढ़ावा देकर। साथ ही, एग्रीटैक जैसी डिजिटल पहलों को तेज करे ताकि किसान वैश्विक मानकों के अनुरूप उत्पादन कर सकें।

असली मकसद तेल व अन्य संसाधनों की लूट

जब सोवियत संघ का पराभव हुआ था, उदारपंथी पूंजीवादी लेखक इसका एलान कर रहे थे कि जनतंत्र की सार्वभौम विजय और स्थिरता का युग आ पहुंचा है। वे समाजवादी चुनौती को अनावश्यक और निरर्थक मानते थे और यह मानते थे कि पूंजीवाद, जो पहले ही अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता दे चुका था तथा सार्वभौम वयस्क मताधिकार एवं उसकी रीढ़ के रूप में कल्याणकारी राज्य के कदमों को ला चुका था, इस चुनौती की नामौजूदगी में मानवता के लिए शांति, आर्थिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने जा रहा है। दूसरी ओर, अनेक वामपंथी लेखक थे, जो निरुपनिवेशीकरण और सार्वभौम वयस्क मताधिकार तथा कल्याणकारी राज्य के कदमों के लाए जाने को, पूंजीवाद के हाथों से झपटी गयी ऐसी रियायतों के रूप में देखते थे, जिन्हें उस समय छीना गया था जब पूंजीवाद, समाजवादी चुनौती के चलते अपने अस्तित्व के लिए ही संकट का सामना कर रहा था। इन वामपंथी लेखकों ने यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया था कि इस चुनौती के पीछे हटने से, पूंजीवादी व्यवस्था फिर से अपने सामान्य लुटेरे रूप में आ जाएगी और इन रियायतों को वापस छीन लेगी। ये बाद वाले लेखक ही सही साबित हुए हैं और साम्राज्यवाद ने—यहां हम उसी की बात करेंगे—अपने नंगे तौर पर हमलावर स्वभाव को प्रदर्शित किया है और उस चीज का प्रदर्शन किया है जिसे उसका लुटेरा दौर ही कहा जा सकता है। अमेरिकी साम्राज्यवाद ने क्या किया है? उसने एक सैन्य कार्रवाई के जरिए, एक अन्य देश के विधिवत निर्वाचित राष्ट्रपति, वेनेजुएला के निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी को उनके घर से अगवा कर लिया है और उन्हें हथकड़ियां डालकर अमेरिका लाया गया है, जहां उन पर ऐसे फर्जी आरोपों में मुकदमा चलाया जा रहा है, जिनके लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य है ही नहीं। और अमेरिका उनके देश पर तब तक सीधे-सीधे अपने उपनिवेश के तौर पर राज करेगा, जब तक कि वह किसी पर्याप्त रूप से अनुकूल सरकार को इस देश पर बैठा नहीं देता है। यह एक अविश्वसनीय धृष्टता की करतूत है, जो अंतरराष्ट्रीय आचरण के सभी कानूनी तथा नैतिक नियमों को पांवों तले रौंदती है और साम्राज्यवाद के इस लुटेरे दौर की ही पहचान कराती है। बहरहाल, यह तो साम्राज्यवाद के लुटेरे दौर की ताजातरीन करतूत भर है। इराक के सद्दाम हुसैन को जबरन सत्ता से हटाया गया तथा फांसी पर लटका दिया गया और वह भी पूरी तरह से फर्जी आरोप लगाकर किया गया। लीबिया के मुअम्मार गद्दाफी की नृशंसता से हत्या कर दी गयी। सीरिया पर कब्जा कर लिया गया। फिलिस्तीनी जनता का नरसंहार किया गया, जबकि उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसे यह मंजूर नहीं है कि साम्राज्यवाद-समर्थित सैटलर औपनिवेशिक परियोजना के जरिए, उसे अपने घरों से बेदखल कर दिया जाए। गज़ा को एक अमेरिकी उपनिवेश के रूप में हाथ में लिया जा रहा है, जिसका शासन डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुना गया वायसराय संभालेगा और गज़ा को एक बेश कीमती अचल संपत्ति के टुकड़े में तब्दील कर दिया जाएगा। ये सभी साम्राज्यवाद के लुटेरे दौर के उन्मुक्त होने की प्रक्रिया में आए प्रकरण हैं। उदारवादी विचारक अब भी, डोनाल्ड ट्रंप को एक सिरफिरे के रूप में लुटेरे की तरह आचरण करने के लिए जिम्मेदार तो मानते हैं, लेकिन हाल की लुटेरी वाली करतूतों की सारी जिम्मेदारी उसी पर डालते हैं। लेकिन, ऊपर बताए गए प्रकरणों में से अधिकांश तो डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले के हैं। ट्रंप और उससे पहले के अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बीच अंतर यही है कि दूसरे राष्ट्रपतियों ने अपनी लुटेरी करतूतों सभ्य लफ्फाजी के आवरण में छुपाने का काम किया था, जबकि ट्रंप अपने प्रशासन के इरादों को छुपाने की कोई कोशिश नहीं करता है। इसके अलावा, पीछे उल्लेखित प्रकरणों में से हरेक में, और इसमें फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार भी शामिल है, अन्य साम्राज्यवादी देशों का पूरा समर्थन हासिल रहा है, जबकि वे अपने कथित उदारवादी सिद्धांतों का ढोल पीटते कभी नहीं थकते हैं। यहां तक कि निकोलस मादुरो के अपहरण को भी, जिसकी दुनिया भर ने निंदा की है, जिसके अपवाद वैश्विक दक्षिण के गिने-चुने देश ही हैं जो ट्रंप को खुश करना चाहते हैं (जिनमें दुर्भाग्य से भारत भी शामिल है), जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन का सक्रिय या मूक समर्थन हासिल है। खासतौर पर अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों द्वारा एक दलील इस तरह की दी जा रही है कि निकोलस मादुरो तो एक तानाशाह शासक था, इसलिए उसके सत्ता से हटाए जाने पर कोई आंसू नहीं बहाए जाने चाहिए। इस दलील का सरासर बेतुकापन साफ देखा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय कानून अमेरिका को और वास्तव में किसी अन्य देश को भी, इसकी इजाजत नहीं देते हैं कि किसी अन्य देश के मामले में सैन्य हस्तक्षेप करे, जिससे वहां जनतंत्र की स्थापना कर सके। यह तय करना तो संबंधित देश की जनता पर ही है कि उसका शासक कौन होगा। इसलिए, अमेरिकी हस्तक्षेप के संदर्भ में यह तो पूरी तरह से ही अप्रासंगिक है कि मादुरो तानाशाह था या नहीं था। इसके अलावा, ट्रंप तो खुद खुलेआम यह स्वीकार कर चुका है कि वेनेजुएला में मादुरो की मुख्य विरोधी, मारिया कोरिना मचाडो को इसके लिए पर्याप्त जनसमर्थन हासिल नहीं है कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वह प्रशासन को संभाल सके। किसी देश में जहां दो राजनीतिक मोर्चे हों, अगर एक को पर्याप्त जनसमर्थन हासिल नहीं है, तो तर्क तो यही कहता है कि दूसरे मोर्चे को उससे ज्यादा समर्थन हासिल होगा। ऐसी सूरत में यह दावा करना, जो दावा खुद ट्रंप ने तथा अनेक यूरोपीय नेताओं ने किया है, कि मादुरो को राजनीतिक वैधता हासिल नहीं थी, पूरी तरह से बकवास है। अगर मचाडो को राजनीतिक वैधता हासिल नहीं है और मादुरो को भी हासिल नहीं है, तब ट्रंप को बताना चाहिए कि वेनेजुएला में राजनीतिक वैधता किसे हासिल है? मादुरो को हटाने का असली कारण ट्रंप ने अपनी खास ठनहुना के साथ खुद ही बता दिया।

शनिवार, 3 जनवरी को अपने संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा- हम बहुत भारी मात्रा में संपदा (वेनेजुएला की) जमीन से निकालने जा रहे हैं। उनका कहना था कि इससे जो पैसा बनेगा वह सिर्फ वेनेजुएला के लोगों के लिए ही नहीं होगा बल्कि अमेरिकी तेल कंपनियों को भी जाएगा और उस देश द्वारा किए गए नुकसानों के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को जाएगा। वह जिन नुकसानों का जिक्र कर रहे थे, ऐसा लगता है कि वेनेजुएला के अपने तेल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करने से हुए कथित नुकसान हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया के दूसरे किसी भी देश से ज्यादा तेल है। उसके संचित तेल भंडार, विश्व के कुल संचित तेल भंडार के 17 फीसद के बराबर बैठेंगे। और वेनेजुएला का तेल लूटने का ट्रंप का प्रस्ताव, खुल्लम खुल्ला यह कबूल करना है कि इस देश को हथियाने और उसे चलाने का यही मकसद है। यह खुली डकैती के सिवा और कुछ नहीं है। चूंकि तुम्हारे पास तेल है, उसे हम हथिया लेंगे। अगर तुम्हारा राष्ट्रपति इसके आड़े आता है तो हम उसका अपहरण कर लेंगे और उसके बाद तुम्हारे देश को या तो सीधे एक उपनिवेश की तरह चलाएंगे या फिर उसकी जगह किसी कठपुतली सरकार को बैठा देंगे, जो हमें तुम्हारे देश को लूटने का मौका देगी। बेशक, दूसरे देशों के संसाधनों को, जिसमें उनकी जमीन या जमीन से मिलने वाले उत्पाद भी शामिल हैं, लूटने का काम साम्राज्यवाद हमेशा से ही करता आया है। यह तो साम्राज्यवाद के केंद्र में ही है। निरुपनिवेशीकरण के बाद उसने लूट की इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, इस काम में अपने आड़े आने वाली सरकारों का तख्तापलट कराने और उनकी जगह पर अपनी फर्माबरदार सरकारें बैठाने की कोशिश की थी। इसके उदाहरणों के रूप में ग्वाटेमाला में अर्बेन्ज, ईरान में मोसद्देह, कांगो में (तब देश का यही नाम था) लुमुम्बा और चिली के एलेंदे के खिलाफ सीआईए-प्रायोजित तख्तापलटों का नाम खुद ब खुद सामने आ जाता है। और अपेक्षाकृत हाल में पूर्वी-यूरोप तथा पूर्व-सोवियत गणराज्यों में करायी गयी विभिन्न रंगीन क्रांतियां और पश्चिम एशिया पर अमेरिकी हमले भी इसी श्रेणी में आते हैं। इन पहले के तमाम मामलों में और वेनेजुएला के मामले में अंतर इसी तथ्य में निहित है कि जहां पहले के मामलों में अमेरिका यह दिखाने की कोशिश करता था कि वह तो एक आंतरिक टकराव में, एक खास पक्ष का साथ दे रहा था, जबकि पर्दे के पीछे वह तख्तापलट कराने के लिए काम कर रहा होता था, लेकिन वेनेजुएला के मामले में उसने सीधे-सीधे सैन्य हस्तक्षेप किया है और इसके लिए, आंतरिक टकराव के किसी एक पक्ष का समर्थन करने के दिखावे की, तिनके की ओट तक नहीं ली गयी है। बेशक, वह ऐसे देशों को भी अपने हमले का निशाना बनाता है जहां साम्राज्यवाद-विरोधी सरकारें हैं, फिर भले ही ये देश खनिज संपदा के मामले में खास संपन्न न हों। ट्रंप ने कुख्यात मुनरो सिद्धांत को पुनर्जीवित करने की अपनी कोशिश के हिस्से के तौर पर क्यूबा, मैक्सिको तथा कोलंबिया को निशाना बनाने के अपने मंसूबों का एलान भी कर दिया है। लेकिन, उसके साम्राज्य के दायरे में लातीनी अमेरिका तथा कैरीबियाई क्षेत्र ही नहीं आते हैं। अमेरिकी दादागीरी से आज तो दुनिया का कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। तथाकथित क्यूबाई मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ ने क्यूबा की हिफाजत की थी, जब अमेरिका ने इस द्वीप देश पर हमले की धमकी दी थी। अमेरिका के साथ नाभिकीय टकराव भड़कने तक का जोखिम लेकर, तब सोवियत संघ ने क्यूबा की हिफाजत की थी। इसी तरह, इससे भी पहले उसने, मिस्र के नेता नासिर द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद, आंग्ल-फ्रांसीसी हमले के खिलाफ मिस्र की हिफाजत की थी। उन दोनों ही मामलों में साम्राज्यवाद को अपने पांव पीछे खींचने पड़े थे। आज सोवियत संघ की कमी दुनिया के ऐसे सभी देशों को बहुत खलने वाली है, जिनके लिए अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवाद से खतरा है।

भारत के लिए यह डील मेक इन इंडिया को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का सबसे बड़ा अवसर

भारत-ईयू समझौते के बाद वियतनाम, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देशों के लिए यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो जाएगी, क्योंकि भारत को मिलने वाली शुल्क छूट उसे एक बड़ा लाभ प्रदान करेगी। यह डील पर्यावरण और श्रम मानकों पर आधारित है, जो भविष्य में अन्य विकासशील देशों के लिए वैश्विक व्यापार के नए मानक तय करेगी। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि भारतीय डेयरी और कृषि क्षेत्र को यूरोपीय गुणवत्ता मानकों के साथ तालमेल बैठाना होगा। साथ ही, घरेलू उद्योगों को यूरोपीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा।भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं में से एक है। यह भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में मील का पत्थर साबित होगा। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह न केवल करोड़ों नौकरियां पैदा करेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र को भी पश्चिम से पूर्व की ओर मजबूती से स्थानांतरित करेगा।

भारत-यूरोपीय संघ के बीच हुई इस ऐतिहासिक मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स ने वैश्विक भू-राजनीति के शांत समुद्र में एक बड़ी लहर पैदा कर दी है। जहाँ भारत और यूरोप इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं, वहीं वाशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद में इसकी प्रतिक्रियाएँ अलग-अलग और काफी दिलचस्प हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने इस डील पर कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिका का तर्क है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। और उसे रिफाइन करके यूरोप को बेच रहा है। अमेरिका के अनुसार, इस डील से यूरोप अनजाने में रूस-यूक्रेन युद्ध के लिए फंडिंग कर रहा है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर 25फीसदी का दंडात्मक टैरिफ लगा रखा है। अब जब ईयू ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर लिया है, तो अमेरिका इसे अपनी नीतियों के खिलाफ एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा है। चीन इस डील को सीधे तौर पर अपने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के वर्चस्व के लिए खतरा मान रहा है। चीन के सोशल मीडिया पर इस डील का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बीजिंग अंदरूनी तौर पर डरा हुआ है। यूरोपीय कंपनियां अब अपनी सप्लाई चेन के लिए चीन पर निर्भरता कम करके भारत को प्राथमिकता देंगी। वहीं चीन इसे ईयू और भारत के बीच एक नए भू-राजनीतिक गठबंधन के रूप में देख रहा है, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना है। अब तक पाकिस्तान को ईयू के जीएसपी प्लस स्टेटस के कारण यूरोपीय बाजारों में भारत पर बढ़त हासिल थी। लेकिन अब, भारत को जीरो-ड्यूटी पहुंच मिलने से पाकिस्तान का नौ अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात सीधे तौर पर खतरे में है। पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि वे भारत की गुणवत्ता और कम लागत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया इसे एक वेक-अप कॉल मान रहा है, क्योंकि उनका देश पहले से ही आर्थिक संकट और आईएमएफ की शर्तों से जूझ रहा है।यह डील दर्शाती है कि भारत अब किसी एक शक्ति (अमेरिका या चीन) के खेमे में बंधने के बजाय अपनी सामरिक स्वायत्तता का उपयोग कर रहा है। वहीं अमेरिका की नाराजगी के बावजूद यूरोप का भारत के साथ आना यह साबित करता है कि वैश्विक भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपन्न हुआ मुक्त व्यापार समझौता जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है, न केवल दोनों क्षेत्रों के आर्थिक भविष्य को नई दिशा देगा, बल्कि वैश्विक व्यापार के शक्ति संतुलन को भी पुनर्व्यवस्थित करेगा। जनवरी 2026 में संपन्न यह ऐतिहासिक समझौता लगभग दो दशकों की लंबी प्रतीक्षा और गहन वार्ताओं का परिणाम है। वैश्विक भू-राजनीति में जब संरक्षणवाद और ट्रेड वॉर की चर्चा गरम है, तब दुनिया की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था भारत और 27 देशों के शक्तिशाली समूह यूरोपीय संघ ने हाथ मिलाकर एक नई मिसाल पेश की है। यह समझौता महज वस्तुओं के आयात-निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दो स्वाभाविक साझेदारों के बीच साझा समृद्धि का एक ब्लूप्रिंट है। भारत के लिए यह डील मेक इन इंडिया को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का सबसे बड़ा अवसर है। टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्न-आभूषण और इंजीनियरिंग सामान जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को यूरोपीय बाजारों में जीरो ड्यूटी की पहुंच मिलेगी। अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में केवल गारमेंट निर्यात दोगुना हो सकता है। भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 45 करोड़ यूरोपीय उपभोक्ताओं का बाजार खुल जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए यूरोप में काम करना सुगम होगा, जिससे रेमिटेंस और सेवा निर्यात में भारी वृद्धि होगी। यूरोप के लिए भारत एक ऐसा विकल्प है जिसे वे चीन के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। लग्जरी कारों (25 लाख से ऊपर), वाइन, स्पिरिट्स और डेयरी उत्पादों पर टैरिफ कम होने से यूरोपीय कंपनियों को भारत के बढ़ते मध्यवर्ग तक सीधी पहुंच मिलेगी।भारत के स्थिर कानूनी ढांचे और इस समझौते के तहत मिलने वाली सुरक्षा से यूरोपीय निवेश एफडीआई की बाढ़ आने की संभावना है। यूरोपीय कंपनियां भारत के सस्ते श्रम और बेहतर संसाधनों का उपयोग कर अपने उत्पादों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बना सकेंगी।चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए यूरोप में काम करना सुगम होगा, जिससे रेमिटेंस और सेवा निर्यात में भारी वृद्धि होगी इस डील से यूरोपीय संघ के लिए कई लाभ हासिल होंगे। उन्हें भारत के रूप में एक विशाल बाजार और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला का आधार मिलेगा।यूरोप के लिए भारत एक ऐसा विकल्प है जिसे वे चीन के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। लग्जरी कारों (25 लाख से ऊपर), वाइन, स्पिरिट्स और डेयरी उत्पादों पर टैरिफ कम होने से यूरोपीय कंपनियों को भारत के बढ़ते मध्यवर्ग तक सीधी पहुंच मिलेगी। भारत के स्थिर कानूनी ढांचे और इस समझौते के तहत मिलने वाली सुरक्षा से यूरोपीय निवेश (एफडीआई) की बाढ़ आने की संभावना है। यूरोपीय कंपनियां भारत के सस्ते श्रम और बेहतर संसाधनों का उपयोग कर अपने उत्पादों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बना सकेंगी।

यह समझौता केवल दो पक्षों तक सीमित नहीं है, इसके वैश्विक प्रभाव दूरगामी हैं। ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीतियों और चीन की दबदबे वाली व्यापार नीतियों के बीच, भारत-ईयू डील ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया अब विकल्प तलाश रही है। इससे वैश्विक सप्लाई चेन की निर्भरता चीन से हटकर भारत की ओर मुड़ेगी। भारत-ईयू समझौते के बाद वियतनाम, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देशों के लिए यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो जाएगी, क्योंकि भारत को मिलने वाली शुल्क छूट उसे एक बड़ा लाभ प्रदान करेगी। यह डील पर्यावरण और श्रम मानकों पर आधारित है, जो भविष्य में अन्य विकासशील देशों के लिए वैश्विक व्यापार के नए मानक तय करेगी। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि भारतीय डेयरी और कृषि क्षेत्र को यूरोपीय गुणवत्ता मानकों के साथ तालमेल बैठाना होगा। साथ ही, घरेलू उद्योगों को यूरोपीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा।भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं में से एक है। यह भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में मील का पत्थर साबित होगा। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह न केवल करोड़ों नौकरियां पैदा करेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र को भी पश्चिम से पूर्व की ओर मजबूती से स्थानांतरित करेगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने चन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पीसनगाना एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/38862)

30 तलबा के सिरों पर बंधी दस्तारे फ़ज़ीलत

मुरादाबाद।

शहर के मशहूर व मारूफ़ इदारे दारुल उलूम जामेउल हुदा गलशाहीद मुरादाबाद का नूरानी व रूहानी सालाना इजलास-ए-आम, खत्म बुखारी शरीफ़ व दस्तारबंदी जेरे सदारत मौलाना मुफ़्ती जावेद अनवर (सदर मुन्ताज़िमा कमेटी), जेरे निगरानी मुफ्ती मोहम्मद तय्यब (नाज़िमे आला) अपनी रिवायती शान व शौकत के साथ मुनाकिद हुआ। जलसे का आगाज़ कारी अब्दुल अहद द्वारा कुराने करीम की तिलावत से हुआ। इसके बाद मोलवी मोहम्मद नौमान बिजनोरी ने

दारुल उलूम जामेउल हुदा गलशाहीद में सजी रूहानी महफिल

शाने अकदस सरकारे ायनात में नजरानायें अकीदत पेश फ़रमाया । इसके बाद जामिया के कदीम तरीन उस्ताद हदीस व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकरामुल्लाह ने खिताब करते हुए दीनी मदारिस की अहमियत और इल्मे दीन और उसकी फ़ज़ीलत पर रौशनी डाली। मौलाना ने फ़रमाया कि अहले ईमान के लिए ज़रूरी है के वह अपने

ब'चों को सबसे पहले मकातिब व मदारिस में भेजकर दीने इस्लाम की बुनियादी तालीम से रोशनाय करायें, ताकि हलाल व् हराम की शनाख्त हो जाये और दीनी मिज़ाज पैदा हो। मौलाना अब्दुल हन्नान कासमी ने अपने खिताब में हाजरीन को किताब व सुन्नत के मुताबिक जिन्दगी गुजारने की तलकीन फरमाई। इस मौके पर दारुल उलूम देवबंद के उस्तादे हदीस हजरत मौलाना खिज़र मोहम्मद कश्मीरी ने भी अपने खिताब में उलेमा, तलबा अवाम व् खवास को नबी, सहाबा-ए-कराम व् बुजुर्गों के तरीके पर चलने की तलकीन फ़रमाई, आखिर में दारुल उलूम देवबंद से तशरीफ़ लाये मौलाना मुफ्ती अब्दुल्लाह मारूफ़ी उस्ताद तबस्सुस फिलहदीस दारुल उलूम देवबंद ने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स दिया। इस मौके पर मदरसे के मुख्तलिफ शौबाजात से फारिग होने वाले ×0 तलबा के सिरों पर दस्तारे फ़ज़ीलत बांधी गयी। जलसे की सरपरस्ती हकीम सय्यद मासूम अली साहब आज़ाद (इमामे शहर) और निजामत मौलाना मुजम्मिल हुसैन ने फ़रमाई । इस मौके पर हाफ़िज़ अब्दुल मालिक, शमशुल हुदा, मौलाना अब्दुल मुईद, मौलाना मोहम्मद जुबैर आलम, मौलाना मोहम्मद याहया, मौलाना हबीबुर रहमान, डॉक्टर निज़ामुद्दीन, कारी अब्दुल्लाह अतहर, हाजी जफर मलिक, हाजी अतहर मलिक, मौलाना उबैदुर रहमान आदि मौजूद रहे।

अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 15 फरवरी तक होंगे आवेदन

मुरादाबाद।

तहसील बिलारी में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित अटल आवासीय विद्यालय में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 में कुल 140 सीट तथा कक्षा 9 में कुल 140 सीटों पर पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी थी जिसे बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। सहायक श्रमायुक्त अजीत कुमार ने बताया कि नवीन संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी, आवेदन पत्र के सत्यापन का कार्य 25 फरवरी, प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 26 से 28 फरवरी, प्रवेश परीक्षा की तिथि 8 मार्च और परीक्षा परिणाम 18 मार्च 2026 को घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग एवं ऑनबोर्डिंग 20 मार्च से 29 मार्च के मध्य संपादित होगी और इस प्रकार नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ 1 अप्रैल 2026 से किया जाएगा।

दो दिवसीय तहसील स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ

मेजा प्रयागराज।

तहसील स्तरीय दो दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को बड़े ही उत्साह और खेल भावना के साथ किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मेजा के तहसीलदार जमुना प्रसाद वर्मा, वरिष्ठ समाजसेवी संजय शुक्ला, समाजसेवी बनारसी लाल सोनकर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एवं वॉलीबॉल को हवा में उछाल कर किया। इस अवसर पर खेल प्रेमियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में ग्रामीण दर्शकों की मौजूदगी ने कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए तहसीलदार जमुना प्रसाद वर्मा ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास का माध्यम हैं, बल्कि युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए ऐसे आयोजन अत्यंत आवश्यक हैं, जिससे क्षेत्र के खिलाड़ी आगे चलकर जिले, प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल को खेल भावना के साथ खेलने और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। प्रतियोगिता में तहसील क्षेत्र की विभिन्न गांवों और टीमों ने भाग लिया। पहले दिन खेले गए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। रोमांचक मुकाबलों के दौरान तालियों और उत्साहवर्धन से पूरा खेल मैदान गूंजता रहा। आयोजकों द्वारा खिलाड़ियों के लिए पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और बैठने की उचित व्यवस्था की गई थी।

आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाना है। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य लोग जयप्रकाश द्विवेदी श्री प्रकाश द्विवेदी रमेश चंद पांडे मुकेश सिंह कृष्ण प्रकाश द्विवेदी हरिकेश तिवारी दिलीप जुगनू प्रेमी बिरजू सोनकर राजकुमार सोनकर विजय शंकर सिंह मुन्ना लाल यादव सहित सैकड़ो की संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का माहौल पूरे क्षेत्र में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता नजर आया।

मनोज ने अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच चोटी पर फहराया तिरंगा

मुरादाबाद। माउंटेनियर रवि कुमार फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में संगठन के सचिव मनोज कुमार ने अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोंच चोटी माउंट किलिमंजारो (ऊँचाई 5895 मीटर) पर गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सफलतापूर्वक फहराकर देश का गौरव बढ़ाया। मनोज कुमार ने बताया कि वे 21 जनवरी को तंजानिया के मोशी शहर पहुँचे और किलिमंजारो नेशनल पार्क से अभियान की शुरुआत की। नेशनल पार्क के मुख्य द्वार से 8 किलोमीटर पैदल यात्रा कर मंदारा हट पहुँचे और रात्रि विश्राम किया। 23 जनवरी को 12 किलोमीटर ट्रेक कर होरोंबो हट पहुँचे और रात्रि विश्राम किया। 24 जनवरी को मौसम, तापमान, ऊँचाई और वातावरण के अनुकूलन के लिए होरोंबो हट से ज़ेब्रा पॉइंट तक चढ़ाई की और पुनः होरोंबो हट पर रात्रि विश्राम किया। 25 जनवरी की सुबह, होरोंबो हट से कठिन और चुनौतीपूर्ण मार्ग पर 9 किलोमीटर की यात्रा कर किबो हट (बेस कैंप) पहुँचे। इसी दौरान मौसम अचानक बिगड़ गया। आधी रात को किबो हट से किलिमंजारो शिखर के लिए प्रस्थान किया, जहाँ मुरादाबाद के लाल मनोज कुमार ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया। अंततः 26 जनवरी को प्रातः 9 बजे, उन्होंने अफ्रीका की सर्वोंच चोटी पर गणतंत्र दिवस मनाते हुए तिरंगा फहराया। यह अभियान मनोज कुमार द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसे अमित कुमार घोष, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पूर्व मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह द्वारा शुभकामनाएँ दी गईं। उल्लेखनीय है कि मनोज कुमार ने इससे पूर्व 22 अगस्त 2025 को रूस स्थित माउंट चेगेट 24 अगस्त 2025 को यूरोप महाद्वीप की सर्वोंच चोटी माउंट एल्ब्रुस अगस्त 2024 में हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति क्षेत्र में 15 अगस्त को युनम चोटी पर कांग यात्से -2 को 25 अगस्त एवं कांग यात्से -1 को 30 अगस्त को सफलतापूर्वक आरोहण किया लगातार 15 दिनों में तीन प्रमुख चोटियों पर सफल आरोहण कर तिरंगा फहराया। मनोज कुमार उत्तर प्रदेश के पहले पर्वतारोही हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की।

कांग्रेसियों ने मनाई जगदेव प्रसाद कुशवाहा की 105वीं जयंती

फतेहपुर।

धन धरती और राजपाट में शोषितों वंचितों की हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करने वाले दूर दर्शी समतावादी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की 105 वीं जयंती आज गाजीपुर कस्बे में हम भारत के लोग बैनर तले भरत मौर्या की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा कि जनता के मुद्दों को नारों में ढालकर 70 के दशक में सामाजिक क्रांति लाने का काम किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व उपाध्यक्ष

सामाजिक न्याय का दिया था नारा-मिस्बाहुल हक़

मिस्बाहुल हक ने कहा कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का विचार सामाजिक न्याय का नारा भूमि और सत्ता का अधिकार एक समतामूलक समाज की स्थापना का रहा है उनका कहना रहा कि समाज मे व्याप्त शोषण बन्द करने के लिए न्याय की खातिर सामन्तवाद के विरूद्ध मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, समता बिना समाज नही, बिना समाज रामराज नही का नारा बाबा साहब डा. भीमराव आंबेडकर के बनाये गये संविधानिक पैरोकार पर स्थापित सहअस्तित्व और बंधुत्व के साथ समतामूलक समाज की स्थापना ही एकमात्र उपाय है ।कार्यक्रम का संचालन करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस अब्दुल हफीज ने आये हुए परतिभागियों का स्वागत करते कहा कि आज के समय मे व्याप्त सामाजिक असंतोष आर्थिक विकास के साथ सामाजिक असमानता की बढती खायीं के लिए कुचक्र जो रचा जा रहा है वह खतरा है हम भारत के लोग जिस स्वतन्त्रता आन्दोलन से उपजी संविधानिक संरक्षण का एक महत्वपूर्ण अस्त्र प्राप्त हुआ है इसी के आधार पर स्थापित संस्थाओं को भेदभाव से मुक्त निरपेक्ष स्वतन्त्र तौर पर काम करना होगा । सभी का आभार व्यक्त करते अति पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को मजबूती से एकतापूर्ण समाज समन्वय के साथ बनाना होगा तभी हम लोग संविधानिक शक्ति पर निर्भर होना चाहिए गोष्ठी मे शहजाद आलम सलीम अख्तर रविन्द्र मौर्य, लवकुश अवध बिहारी रैदास संतोष कुलजीत मौर्य और निहाल अहमद ने भाग लिया।

बिहार के रायपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रईस सिद्दीकी समेत पांच कवियों को सम्मानित किया

बहराइच। बिहार के रायपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बहराइच और बलरामपुर से पटना में आयोजित दो दिवसीय बिहार साहित्य महोत्सव में आमंत्रित देश के मशहूर शायर रईस सिद्दीकी बहराइची, कवि पी.के. प्रचंड, शायर काशिफ नानपारवी, डॉ. सगीर सिद्दीकी और शाद बलरामपुरी को अपने राजभवन (लोक भवन) का अतिथि बनाया। साथ ही, उन्होंने लगभग एक घंटे तक अपने चैंबर में बुलाकर अत्यंत स्नेहपूर्ण और दिलो बातचीत की। उन्होंने बहराइच का हाल-चाल पूछा और बहराइच के साहित्यिक माहौल पर भी चर्चा की। प्रसिद्ध शायर रईस सिद्दीकी बहराइची की अगुवाई में शामिल डॉ. शाद बलरामपुरी, पी.के. प्रचंड, डॉ. सगीर सिद्दीकी बहराइची और काशिफ नानपारवी को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। रईस सिद्दीकी ने गुफ्तगू प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित देश के 21 ग़ज़लकार पुस्तक भेंट की, जिसमें उनकी तीस ग़ज़लें शामिल हैं। साथ ही अवध वाटिका की ग़ज़ल संग्रह और शाद बलरामपुरी ने भी अपनी रचनाओं का संग्रह रायपाल आरिफ मोहम्मद खान को भेंट किया। मुलाकात के बाद राजभवन से सुविधा उपलब्ध कराते हुए पटना गेस्ट हाउस में ठहरने और भोजन की व्यवस्था कराई गई। दूसरे दिन राजभवन में दोबारा भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। पांचों साहित्यकारों को अत्यंत वीआईपी व्यवस्था से नवाजा गया और स्टेशन तक छोड़ने की सुविधा भी गवर्नर हाउस से उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर रायपाल के ओएसडी अनिल कुमार सिंह, बड़े साहबजादे मुस्तफा आरिफ और पर्सनल असिस्टेंट शैलेंद्र से भी मुलाकात का मौका मिला। बहराइच के साहित्यकारों, शायरों और कवियों से इस तरह की मुलाकात का यह पहला अवसर था। इसकी जानकारी मिलते ही जिले के शायरों-कवियों ने खुशी व्यक्त करते हुए सभी सम्मानित शायरों कवियों को बधाई दी है। उर्दू महफ़िल अदबी तंज़ीम बहराइच और अवध वाटिका साहित्य संस्थान के सभी पदाधिकारियों ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी है।

दिल्ली में 1047 जल निकायों के बावजूद नमभूमियां संकट में, 30 साल में 9 प्रतिशत हिस्सा खत्म

नई दिल्ली । राजधानी की नमभूमियों की स्थिति चिंताजनक बनी है। दिल्ली में कई जल निकाय और नमभूमियां मौजूद हैं, लेकिन किसी को भी रामसर सूची में शामिल नहीं किया है। कानूनी संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय मान्यता की कमी इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्रों की सुरक्षा में बड़ी बाधा बन रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, निर्माण और प्रदूषण इन जल निकायों और नमभूमियों को खतरे में डाल रही है। हाल के अध्ययन और रिमर्च से पता चलता है कि पिछले कई साल में इन जल निकायों और नमभूमियों का क्षेत्र लगातार घटा है। इसके कारण जैव विविधता और पानी के प्राकृतिक संसाधनों पर गंभीर असर पड़ रहा है। दिल्ली में नमभूमियों की कुल संख्या भले ही हजारों में हो, लेकिन कानूनी संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय मान्यता की कमी इनकी सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के एक नए अध्ययन में खुलासा हुआ है कि बीते 30 वर्षों में दिल्ली की नमभूमि का लगभग 9 प्रतिशत हिस्सा खत्म हो गया, जबकि दक्षिणी दिल्ली में यह गिरावट 97 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह अध्ययन एनसीएल टेक और टेरना ग्लोबल बिजनेस स्कूल के सहयोग से किया गया। इसमें 1991 से 2021 तक के उपग्रह आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिससे राजधानी के जल निकायों और हरित क्षेत्रों में आई गिरावट का पता चला। अध्ययन के अनुसार, दिल्ली में नमभूमि क्षेत्र 2000 में 32.9 वर्ग किमी से घटकर 2022 में 30.2 वर्ग किमी रह गया।

नजफगढ़ झील और संजय झील सिकुड़ीं

एक अध्ययन के अनुसार, नजफगढ़ झील, भलस्वा झील और हौज खास जैसी प्रमुख नमभूमियां तेजी से सिमट रही हैं। संजय झील अब चारों ओर से निर्माणों में घिर गई है।

हालांकि, नई दिल्ली क्षेत्र में जल आवरण थोड़ा बढ़ा है। इसमें 2011 के 0.012 से 2021 में 0.49 फीसदी, जो नियोजित पुनर्स्थापन परियोजनाओं का परिणाम है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की आबादी 1951 में 14.7 लाख से बढ़कर 2023 में करीब 3.3 करोड़ हो गई है। इसी दौरान शहर का क्षेत्रफल 201 वर्ग किमी से बढ़कर 1,467 वर्ग किमी तक फैल गया। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस तेज विस्तार ने प्राकृतिक जल प्रणालियों पर भारी दबाव डाला है, जिससे यमुना नदी और उसके बाढ़ मैदान भी संकुचित हो गए हैं।

यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क उम्मीद की किरण

इन चुनौतियों के बीच यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क उम्मीद की किरण बना हुआ है। दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स की तरफ से विकसित यह पार्क यमुना नदी के बाढ़ का मैदान को पुनर्स्थापित करने का सफल उदाहरण है। पार्क में प्राकृतिक आर्द्रभूमियां, घास के मैदान, वन क्षेत्र और नदी तटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल किया गया है। यह भूजल रिचार्ज, बाढ़ नियंत्रण, जल और जल गुणवत्ता सुधार और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित

नई दिल्ली ।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा चीन से जुड़े मुद्दे पर एक पत्रिका (मैगजीन) की रिपोर्ट का हवाला देने की कोशिश के बाद सोमवार को सदन में नया विवाद खड़ा हो गया. बताया गया कि जिस रिपोर्ट का राहुल गांधी उल्लेख कर रहे थे, उसमें पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे (सेवानिवृत्त) की अप्रकाशित किताब से जुड़े कथित उद्धरण शामिल थे. स्पीकर ने सदन के नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को ऐसा करने से रोक दिया. सत्ता पक्ष ने इसे सदन की मर्यादा और नियमों से जोड़ते हुए नेता विपक्ष पर सवाल खड़े किए, वहीं विपक्ष का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा

और चीन जैसे मुद्दों पर चर्चा से रोकना सही नहीं है. घटनाक्रम के चलते कुछ देर के लिए सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया और सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. इसके बाद बहस और ज्यादा आक्रामक होने लगी तो स्पीकर ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही को 4 बजे तक स्थगित कर दिया. कार्यवाही फिर शुरू होते ही एक बार फिर राहुल ने वही मुद्दा उठाया तो फिर से सदन में हंगामा

राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा जरूरी, सेना का सच छुपाना ठीक नहीं, लोकसभा में हंगामे के बाद बोले राहुल गांधी

होने लगा. जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने बाहर मीडिया से कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा जरूरी है. उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह के बारे में नरवणे ने अपनी किताब में साफ लिखा है,. लेकिन मुझे इस पर बोलने नहीं दिया जा रहा है।

अजीत पवार की मौत हादसा नहीं साजिश, संजय राउत ने न्यायमूर्ति लोया केस से जोड़ा, सीबीआई जांच की मांग

मुंबई।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत पर सवाल उठाते हुए विमान दुर्घटना में साजिश की आशंका जताई। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो विरोधी गुटों के बीच संभावित सुलह की अटकलें तेज हैं।

राउत ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित एनसीपी विलय का समर्थन करने के बाद अजीत पवार पर दबाव डाला गया और दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सिंचाई घोटाले की फाइलों का इस्तेमाल उन्हें धमकाने के लिए किया। राउत के अनुसार, इस घटना के कुछ ही दिनों के भीतर अजीत पवार की अचानक मौत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि अजीत दादा की दुर्घटना पर सवाल जरूर उठेंगे... सवाल उठने ही चाहिए।

जिस तरह से अजीत पवार जैसे नेता... महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई और जो तथ्य सामने आ रहे हैं - इसकी जांच होनी चाहिए... मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है।

उन्होंने आगे कहा, पर्दे के पीछे कुछ जरूर हुआ है... उनकी रहस्यमय तरीके से 10 दिनों के भीतर मृत्यु हो गई। इससे हम क्या समझते हैं? यह हमें न्यायमूर्ति लोया की याद दिलाता है।

एनसीपी नेताओं ने भी संदेह जताया

इससे पहले, एनसीपी नेता अमोल मितकारी ने भी इसी तरह के संदेह व्यक्त किए थे, जिसमें उन्होंने अचानक पायलट परिवर्तन, विमान के मार्ग में बदलाव और दुर्घटनास्थल से बरामद शवों की स्थिति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा, एक भी कागज नहीं जला, लेकिन शव जले हुए थे। इससे संदेह पैदा होता है। मितकारी ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच शुरू करने का आग्रह किया है और उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप की भी मांग करेंगे।

परिवार ने संयम बरतने की अपील की

राजनीतिक तूफान के बावजूद, एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने सभी से इस त्रासदी का राजनीतिकरण न करने की अपील की और जोर देकर कहा कि यह दुर्घटना एक हादसा थी। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने 28 जनवरी को बारामती में विमान के उतरने के प्रयास के दौरान अजीत पवार, उनके सुरक्षा अधिकारी, एक फ्लाइट अटेंडेंट और दो पायलटों की जान लेने वाली इस दुर्घटना की औपचारिक जांच शुरू कर दी है।

बंग भवन के पास दिल्ली पुलिस से भिड़ गईं ममता, एसआईआर पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता की मांग

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दिल्ली के बंगा भवन के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों का सामना किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में किसी आंदोलन के लिए नहीं आई हैं। उनका मकसद चुनावी सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाना है। ममता बनर्जी रविवार को दिल्ली पहुंची थीं। इसके बाद वो बंगा भवन गईं, जो दिल्ली में पश्चिम बंगाल सरकार का गेस्ट हाउस है। वहां वे परिवार ठहरे हुए हैं जो बंगाल में चुनावी सूची की जांच प्रक्रिया से प्रभावित हुए हैं। इमारत के बाहर भारी पुलिस बल तैनात देखकर मुख्यमंत्री नाराज हो गईं।

उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से कहा कि वे बंगाल के लोगों के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगा भवन में बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से कहा, हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमारी चुनाव आयोग के साथ बैठक तय है। लोग परेशान हैं, क्या उनके परिवार मीडिया से बात भी नहीं कर सकते? मुख्यमंत्री ने कहा, जहां भी एसआईआर से प्रभावित परिवार ठहरे हैं, वहां दिल्ली पुलिस तैनात है। जब दिल्ली में धमाका होता है तो दिल्ली पुलिस कहां होती है?

केंद्र पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने कहा मैं दिल्ली पुलिस को दोष नहीं देती, मैं उन लोगों को दोष देती हूं जो शीर्ष पर हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग देश की रक्षा करने में नाकाम हैं और आम लोगों पर एसआईआर के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली की तुलना एक जमींदारी से की, जहां गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। ममता बनर्जी ने पुलिसकर्मियों से कहा, मैं यहां किसी आंदोलन के लिए नहीं हूं। अगर मैं आंदोलन करने पर आती, तो आप अपना हेलत खो देते। उन्होंने मांग की कि दिल्ली पुलिस इन परिवारों को परेशान करना बंद करे। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भी मुलाकात करेंगी। उन्होंने इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है।

पूर्व मंत्री और बीजेपी एमएलए के बयान से हलचल, बोले- सारे नियम,कानून ब्राह्मणों के खिलाफ बन रहे

सागर ।

मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि राजनीति और बयानबाजी ब्राह्मणों की ओर घूम गई है। अधिकारियों से लेकर नेता सभी ब्राह्मण वर्ग को लेकर अलग-अलग बयान देते नजर आ रहे हैं। अब प्रदेश बीजेपी के सीनियर और तेज तर्रार नेताओं में शामिल गोपाल भार्गव ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि सारे नियम और कानून ब्राह्मणों के खिलाफ ही बन रहे हैं।भार्गव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में ब्राह्मणों को पीछे धकेला जा रहा है। दरअसल सागर में ब्राह्मण समाज मेधावी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को कौटिल्य सम्मान से सम्मान देकर नवाजा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व विधायक गोपाल भार्गव थे। इस मौके पर भार्गव ने ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज

संवैधानिक व्यवस्था में ब्राह्मणों को पीछे धकेला जा रहा

आईएएस निशांत खरे ने ब्राह्मणों को लिए आरक्षण का मांग की है। इसके अलावा पूर्व आईएएस मनोज श्रीवास्तव ने भी ब्राह्मणों के हक के लिए मोर्चा खोला है। अब गोपाल भार्गव ने यह कहकर हलचल मचा दी है कि सारे कानून ब्राह्मणों के खिलाफ बन रहे हैं। आपको बता दें कि ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन रविवार को रविंद्र भवन में हुआ था जिसको अध्यक्षता एसकेवीएन विवि के संस्थापक कुलपति डॉ. अनिल तिवारी ने की। तिवारी ने कहा कि ये विवाह स्मारिका और सम्मान समारोह सरकार और उनके नुमाइंदों को जागरूक करने के लिए आयोजित होते हैं।

सारे समाज और वर्ग एक हैं और संगठित हैं,इसलिए उनकी सुनी जाती है लेकिन हम बिखरे हुए हैं, वोट बैंक नहीं हैं। भार्गव ने कहा इसलिए संवैधानिक व्यवस्था में हम पीछे धकेले जा रहे हैं। इस मौके पर विधायक गोपाल भार्गव ने एक बड़ी अपील की है। भार्गव ने कहा कि सारे नियम ब्राह्मणों के खिलाफ बन रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण पुरातन काल से ही धर्म के प्रदर्शक रहे हैं तो लोग सनातन धर्म पर ही हमला करने लगे हैं। लेकिन अब समय आ गया है हमें धर्म बचाने के लिए एक होना ही पड़ेगा। गौर करने वाली बात है कि मध्यप्रदेश में ब्राह्मणों पर लगातार टिप्पणियां सामने आ रही हैं। सबसे पहले आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादित बोला था। वहीं दूसरी ओर रिटायर्ड

प्रधानमंत्री मोदी इसी माह कर सकते हैं नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन संभवतः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसी माह कर सकते हैं। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारा हवाई अड्डा तैयार है। हवाई अड्डे के लाइसेंस से संबंधित औपचारिकताएं अंतिम चरण में हैं। मुझे विश्वास है कि इसी माह प्रधानमंत्री द्वारा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा। यह हवाई अड्डा यश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित की जा रही एक greenfield परियोजना है। लगभग 1,300 हेक्टेयर में फैली इस परियोजना का पहला चरण सितंबर 2024 में शुरू होना था, लेकिन काम पूरा नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हो सका और कई बार इसकी समयसीमा बढ़ाई गई।

धर्मांतरण कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और 12 राज्यों से मांगा जवाब

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 फरवरी 2026) को धर्मांतरण रोधी कानूनों को लेकर एक अहम सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और देश के 12 राज्यों को नोटिस जारी किया है।

यह मामला नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया की ओर से दायर नई जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें कई राज्यों के Anti-Conversion Laws को संविधान के खिलाफ बताया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संवेदनशील मुद्दे की आगे की सुनवाई अब तीन जजों की संविधान पीठ द्वारा की जाएगी। NCCI की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत को बताया कि कई राज्यों में लागू धर्मांतरण कानूनों का व्यापक दुरुपयोग किया जा रहा है।

उनका तर्क था कि इन कानूनों के चलते आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों—अनुच्छेद 14 (समानता), 21 (जीवन व स्वतंत्रता) और 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों के कानून ऐसे हैं, जो समूहों को शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे बिना ठोस आधार के FIR, पुलिस कार्रवाई और उत्पीड़न बढ़ रहा है। इसी आधार पर

याचिकाकर्ताओं ने इन कानूनों पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की मांग की।

केंद्र सरकार की दलील

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार अपना जवाब जल्द दाखिल करेगी। उन्होंने दलील दी कि ये कानून पहले से मौजूद सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच के पुराने फैसलों के दायरे में आते हैं। इस पर मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत का ध्यान ओडिशा और राजस्थान में हालिया संशोधनों की ओर दिलाया और कहा कि ये नए बदलाव पहले की याचिकाओं में शामिल नहीं थे। उन्होंने सभी राज्यों के स्थायी अधिवक्ताओं को औपचारिक नोटिस देने की मांग भी की।

किन राज्यों को भेजा गया नोटिस?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा जिन 12 राज्यों को नोटिस जारी किया है, वे हैं– राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। अदालत ने निर्देश दिया है कि नोटिस की प्रति संबंधित राज्यों के महाधिवक्ताओं को भी भेजी जाए। साथ ही सभी राज्य चाहें तो संयुक्त जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इन कानूनों की संवैधानिक वैधता से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सितंबर 2025 में भी अदालत ने कुछ मामलों में राज्यों से जवाब तलब किया था। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अदालत अंतरिम राहत देती है या नहीं। यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य की कानून व्यवस्था के बीच संतुलन की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है।

लखनऊ में सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले- यह कर्तव्य भवन से आया पहला बजट

लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार (2 फरवरी) को लखनऊ में केंद्रीय बजट 2026-27 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस काल्पनिक बजट के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। पिछले 11 सालों में हमने जो यात्रा तय की है उसको बदौलत जो नीतियां तय हुई उसी का परिणाम है कि 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से उभरकर भारत की प्रगति में योगदान दे रहे हैं... ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से बनकर सामने आया है। हर भारतीयों को अपने कर्तव्यों का एहसास कराने का भी बजट आग्रह कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एमएसएमई, स्टार्टअप और स्वदेशी उत्पादन को समर्थन देकर आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत किया गया है।

योगी ने भरोसा जताते हुए कहा, पूर्ण विश्वास है कि सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और सुशासन के माध्यम से यह बजट वर्तमान के साथ भविष्य के भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपायों की घोषणा की, वैश्विक डेटा केंद्रों के लिए दीर्घकालिक कर प्रोत्साहन की पेशकश की और कृषि और पर्यटन के लिए समर्थन की घोषणा की। उन्होंने 2026-27 के लिए 53.5 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय बजट पेश किया, जिसे बढ़ते वैश्विक जोखिमों के बीच विकास को बनाए रखने के लिए एक दीर्घकालिक खाका के रूप में देखा जा रहा है।

अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया

नई दिल्ली । अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25फीसदी रेसिप्रोकल (जैसे को तैसा) टैरिफ को 7फीसदी घटाकर 18फीसदी कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोमवार को सोशल मीडिया 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट करके इसके बारे में जानकारी दी। हालांकि रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाए गए 25फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। लेकिन ट्रम्प ने यह भी कहा कि पीएम मोदी रूसी तेल खरीदना बंद करके अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा- यह जानकार खुशी हुई कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटकर 18फीसदी हो जाएगा। अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत पर दो बार टैरिफ लगाया था। पहली बार 1 अगस्त को व्यापार घाटे को लेकर 25फीसदी टैरिफ लगाया गया। इसके बाद 27 अगस्त को रूस से तेल खरीदने की वजह से 25फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। ट्रम्प ने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा- आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अपने देश के एक मजबूत और सम्मानित नेता हैं।

25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ पर कोई ऐलान नहीं; ट्रम्प बोले- मोदी रूसी तेल खरीदना बंद करेंगे

हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें व्यापार और रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का विषय भी शामिल था। बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने सहमति जताई कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और अमेरिका से कहीं ज्यादा तेल खरीदेगा। इसके अलावा वेनेजुएला से तेल खरीदने की संभावना पर भी बात हुई। मेरा मानना है कि इससे यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी, जहां हर

हफ्ते हजारों लोगों की जान जा रही है। पीएम मोदी की दोस्ती और सम्मान में और उनके अनुरोध पर, हमने अमेरिका और भारत के बीच तुरंत एक व्यापार समझौते पर सहमति बनाई है। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाया जाने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25फीसदी से घटाकर 18फीसदी करेगा। वहीं भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को घटाकर शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 'बाय अमेरिकन' को लेकर भी बड़ी प्रतिबद्धता जताई है। इसके तहत भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से ज्यादा के ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदेगा। भारत के साथ हमारा रिश्ता आगे और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री मोदी और मैं दोनों ऐसे लोग हैं जो काम करके दिखाते हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि मुझे राष्ट्रपति ट्रम्प से बात करके बहुत खुशी हुई। यह जानकर बेहद संतोष है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18फीसदी कर दिया गया है। इस शानदार फैसले के लिए मैं भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रम्प का दिल से धन्यवाद करता हूं। जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश मिलकर काम करते हैं, तो इसका सीधा फायदा हमारे लोगों को मिलता है और आपसी सहयोग के नए और बड़े मौके खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प का नेतृत्व बेहद अहम है। शांति के लिए उनके प्रयासों का भारत पूरी तरह समर्थन करता है।

मैं उनके साथ मिलकर काम करने और भारत-अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने को लेकर उत्सुक हूं। ट्रम्प ने आज ही अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर भारत से जुड़ी दो तस्वीरें पोस्ट की थी। एक में उन्होंने इंडिया गेट की फोटो शेयर की थी, जबकि दूसरे में पीएम मोदी के साथ एक मैगजीन का कवर शेयर किया था।